न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और एन सी खिच्ची के समक्ष,

डॉ. बी.डी. गुप्ता और अन्य - अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती. आर. रानी मनोरंजीथम और अन्य-प्रतिवादी

1999 का एफ.ए.ओ. नंबर 952
12 दिसंबर, 2000

मोटर वाहन अधिनियम, 1988–धारा. 110-ए-ड्राइवरों की लापरवाही और जल्दबाजी के कारण दुर्घटना में 23 वर्षीय छात्र की मृत्यु-मृतक ने अपना 4 1/2 वर्ष का एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा किया, इंटर्नशिप कर रहा था और रु. 2,000/- प्रतिमाह उस समय वजीफे के रूप में - ट्रिब्यूनल ने मुआवजे का आकलन 2,40,000/- रुपये में किया। 10 का गुणक लागू करके अंशदान लेते हुए रु. 2,000/- प्रति माह अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए वेतन का एक तिहाई हिस्सा काटने के बाद - ट्रिब्यूनल ने उनके करियर की प्रगति के प्रॉस्पेक्टस को नजरअंदाज कर दिया - मासिक आय रुपये 12,000/- प्रति माह से कम तय करना अनुचित है। - 12 का गुणक लागू किया जाएगा - 11,52,000/-रुपये पर मुआवजे का आकलन करते समय अपील की अनुमति दी गई।

अभिनिर्धारित किया कि अप्रैल, 1995 में मृतक इंटर्नशिप से गुजर रहा था। उन्हें रुपये 2000/- का वजीफा मिलता था। हालाँकि, स्नातक स्तर की पढ़ाई पर, वह आसानी से एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने या निजी प्रैक्टिस स्थापित करने की उम्मीद कर सकते थे। वह पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते थे. इनमें से किसी भी स्थिति में, उसकी आय रुपये 3000/- प्रति माह तक सीमित नहीं होती। जैसा कि ट्रिब्यूनल द्वारा मूल्यांकन किया गया है। दरअसल, वर्ष 1995-96 में, उच्च अध्ययन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में शामिल होने वाले जूनियर रेजिडेंट्स को रुपये 12000/- प्रति माह या अधिक का भुगतान किया गया था। जिन लोगों को राज्य चिकित्सा सेवाओं में नियुक्ति के लिए चुना गया, उन्हें और

भी अधिक भुगतान किया गया। कैरियर में उन्नति के प्रॉस्पेक्टस थे। इस आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की मासिक आय रुपये 12000/- प्रति माह से कम तय करना अनुचित होगा। यदि इस राशि का एक तिहाई हिस्सा मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के रूप में हटा दिया जाए, तो वह आसानी से उसके माता-पिता के लिए 8000/- प्रति माह रुपये बचा सकता था।

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय जिस मुख्य सिद्धांत का पालन करते हैं वह यह है कि नुकसान को कम से कम किया जाना चाहिए। फिर भी, हम ज़मीनी हक़ीक़तों से नज़रें नहीं चुरा सकते। यह निर्विवाद है कि जीवन प्रत्याशा वर्षों के साथ बढ़ रही है। इससे भी आगे, भले ही मृतक की शादी हो गई हो, सामान्य घटनाक्रम में वह अपने माता-पिता की देखभाल करता रहेगा और उनका भरण-पोषण करता रहेगा। कम से कम वह उनके लिए मदद और सांत्वना का स्रोत भी होता। हादसे के वक्त मृतक के पिता की उम्र करीब 60 साल थी जबकि मां की उम्र 58 साल से कम थी. ऐसा भी नहीं लगता कि मृतक के माता-पिता स्वस्थ एवं निरोग नहीं हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, हम 12 का गुणक लागू करना उचित समझते हैं।

अशोक शर्मा, याचिकाकर्ता के वकील
सुवीर दीवान, प्रतिवादी संख्या 5 के वकील
गोपाल मित्तल, प्रतिवादी संख्या 6 के वकील

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता, (मौखिक)

(1) अपीलकर्ता दुर्भाग्यपूर्ण माता-पिता हैं जिन्हें अपने युवा बेटे - डॉ. विक्रांत गुप्ता की मृत्यु से अपूरणीय क्षति हुई है। वह 23 साल का था और उसने हाल ही में मेडिसिन और सर्जरी में स्नातक किया था। वह इंटर्नशिप कर रहा था. एक लॉरी दुर्घटना में उनका अंत हो गया। मृत्यु तत्काल थी. अपीलकर्ताओं ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने कुल 2,70,000/- रूपये की राशि का आकलन किया और अवार्ड दिया। अपीलकर्ताओं की शिकायत है कि मुआवजा बहुत कम है। इसलिए यह अपील।

(2) तथ्यों पर संक्षेप में गौर किया जा सकता है।

(3) 21- 22 अप्रैल, 1995 की मध्यरात्रि को, विक्रांत गुप्ता लॉरी संख्या टीसीजी-2400 में पांडिचेरी की यात्रा कर रहे थे। चेंगलपट्टू के पास, लॉरी ने एक स्थिर ट्रक संख्या PY-01-0477 को टक्कर मार दी, जो बिना किसी रोशनी या संकेत के सड़क के गलत तरफ खड़ा था। विक्रांत गुप्ता को कई चोटें आईं और उनकी मौत हो गई। उनका पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज, चेंगलपट्टू में किया गया। एक एफआईआर पूर्व. पी.5 भी रिकार्ड किया गया।

(4) मृतक के पिता चंडीगढ़ में थे। वह वर्ष 1994 में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के रेडियोथेरेपी विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। 22 अप्रैल, 1995 को उन्हें मंगोलिया के लिए रवाना होना था। उनका टिकट पहले ही बुक हो चुका था। हालाँकि, टेलीग्राम प्राप्त होने पर, वह मद्रास के लिए उड़ान भर चुके थे और फिर चेंगलपट्टू पहुँचे। उन्होंने शव का एंबॉल्म कराया। इसे हवाई मार्ग से दिल्ली और फिर एंबुलेंस से चंडीगढ़ ले जाया गया। अंतिम संस्कार चंडीगढ़ में किया गया।

(5) मृतक का अकादमिक रिकॉर्ड शानदार था। वह जुलाई, 1990 में जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पांडिचेरी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल हुए थे। यह प्रवेश उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित चयन के परिणामस्वरूप दिया गया था। उन्होंने साढ़े चार साल का कोर्स पूरा कर लिया था और जनवरी 1995 से इंटर्नशिप कर रहे थे। इंटर्नशिप की अवधि के दौरान उन्हें रुपये 2000 का मासिक वजीफा दिया जा रहा था। दुर्घटना ने एक आशाजनक करियर का अंत कर दिया।

(6) मृतक के अन्य हित भी थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक से क्लासिकल गिटार में ग्रेड-V की परीक्षा पास की थी। उनके पास चिकित्सा पेशे के अलावा संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने की महत्वाकांक्षी योजनाएँ थीं।

(7) अपीलकर्ताओं का दावा है कि मृतक के पास न्यूनतम रुपये 50,000/- प्रति माह कमाने की क्षमता थी। इस आधार पर 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा. 18% ब्याज सहित 20 लाख का दावा किया गया।

(8) याचिका में, दो वाहनों के मालिक और चालक और बीमाकर्ता अर्थात। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पार्टियों के रूप में शामिल किया गया था। दो कंपनियां सामने आईं. दूसरों ने नहीं किया. परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 और 7 पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

(9) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर लिखित बयान में, यह कहा गया था कि कोई वादहेतुक नहीं उत्पन्न हुआ है कथित दुर्घटना के समय पहला प्रतिवादी वाहन का मालिक नहीं था। उसका कोई बीमा योग्य हित नहीं था और ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। गुण-दोष के आधार पर, मूल दलील यह थी कि दावेदारों को सबूत पेश करने को कहा जाए। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी-प्रतिवादी नंबर 6 की ओर से दायर किया जवाब भी इसी तरह का थी।

(10) पार्टियों की दलीलों पर, ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित तीन मुद्दे तय किए: -

1- क्या प्रश्नगत दुर्घटना प्रतिवादी क्रमांक 2 और 4 की तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी? ओपीपी.

2. यदि मामला संख्या 1 सिद्ध हो जाता है, तो दावेदार किस राशि के मुआवजे के हकदार हैं और किससे? ओपीपी.

3. राहत.

(11) अंक संख्या 1 पर, ट्रिब्यूनल ने पाया कि दुर्घटना "प्रतिवादी संख्या 2 और 4 के जल्दबाजी और लापरवाही भरे कृत्यों के कारण" हुई थी। मुआवजे की मात्रा पर ट्रिब्यूनल का मानना था कि इंटर्नशिप पूरी होने के बाद मृतक का वेतन रु.3000 व्यक्तिगत खर्चों के कारण प्रति तिहाई की कटौती की गई। इस प्रकार, अंशदान रु. 2000 प्रति माह, ट्रिब्यूनल ने 10 का गुणक लागू किया और रुपये 2,40,000. पर मुआवजे का आकलन किया। इसने रुपये की एक और राशि की अनुमति दी। परिवहन

शुल्क के कारण 20,000 रुपये। दाह संस्कार के लिए 10,000 रु. इस प्रकार, कुल मुआवजा रु. 2,70,000 का मूल्यांकन कर अवार्ड पारित किया गया।

(12) अपीलकर्ताओं के वकील श्री अशोक शर्मा का तर्क है कि ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित मुआवजा बेहद अपर्याप्त है और बहुत अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए था। दूसरी ओर, बीमाकर्ता प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के विद्वान वकील एम/एस सुवीर दीवान और गोपाल मित्तल ने (हालाँकि आधे-अधूरे मन से) तर्क दिया है कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया मुआवजा पर्याप्त है।

(13) विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह है - क्या ट्रिब्यूनल ने दावेदारों को उचित और न्यायसंगत मुआवजा दिया है?

(14) माना कि मृतक ने एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। प्रमाणपत्र प्रदर्शनी-1 से साफ पता चलता है कि वह अपनी इंटर्नशिप कर रहा था। यह भी स्पष्ट है कि वह "एक बहुत अच्छा छात्र था और उसने पहली परीक्षा में ही सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली थीं"। उनका पूर्व रिकॉर्ड भी अच्छा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप उन्हें जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पांडिचेरी में प्रवेश मिला था। इसके अलावा, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ़ म्यूज़िक से ग्रेड V की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी।

(15) डॉ. बी.डी. गुप्ता-मृतक के पिता PW-1 के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की "चिकित्सा पेशे में अपना समय समर्पित करने के अलावा संगीत कार्यक्रम करने की महत्वाकांक्षी योजना थी..." उन्होंने यह भी कहा कि मृतक को "अपने एमडी/एमएस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना था और जीवन में ऊंचा उठना था..." .'' जिरह में गवाह को केवल यही सुझाव दिया गया कि उसका बेटा एमबीबीएस नहीं है। अन्यथा, ऐसा कुछ भी सुझाव नहीं दिया गया जिसका मृतक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(16) यह स्पष्ट है कि मृतक का शैक्षणिक रिकॉर्ड लगातार अच्छा था। मेडिकल पाठ्यक्रम में उनका चयन और प्रवेश उनकी अच्छी शैक्षणिक

उपलब्धियों का प्रतीक है। भले ही पिताजी की गवाही को कुछ हद तक रुचि के आधार पर दूषित माना जाता है (हालाँकि ऐसा कोई संकेत नहीं है), हमारे पास संस्थान के डीन की स्पष्ट राय है। उन्होंने वादे और क्षमता की एक तस्वीर पेश की है। प्रमाणपत्र प्रदर्शनी-1 इससे पता चलता है कि मृतक ने न केवल पहले प्रयास में सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की थीं, बल्कि यह भी कि "यदि वह जीवित रहता, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वह अध्ययन के उच्च पाठ्यक्रमों (जैसे एम.डी., एम.एस., आदि) में प्रवेश पा सकता था।" और एक विशेषज्ञ चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अच्छी आय पाने के योग्य हैं।" जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पांडिचेरी के डीन का यह आकलन मृतक की क्षमता का स्पष्ट प्रमाण देता है। जाहिर है, उसका अतीत अच्छा था और भविष्य भी उज्ज्वल होने की संभावना थी। उसमें अपने माता-पिता के लिए आराम का स्रोत और समाज के लिए संपत्ति बनने की क्षमता थी।

(17) यह सत्य है कि अप्रैल 1995 में मृतक इंटर्नशिप कर रहा था। उन्हें रुपये 2000 का वजीफा मिलता था। हालाँकि, स्नातक स्तर पर वह आसानी से एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने या निजी प्रैक्टिस स्थापित करने की उम्मीद कर सकते थे। वह पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकता था। इनमें से किसी भी स्थिति में, उसकी आय ट्रिब्यूनल द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 3,000 रुपयेप्रति माह तक सीमित नहीं होती। वास्तव में, यह स्वीकृत स्थिति है कि वर्ष 1995-96 में भी, उच्च अध्ययन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में शामिल होने वाले जूनियर रेजिडेंट्स को रुपये 12,000 प्रति माह या अधिक का भुगतान किया गया था। जिन लोगों को राज्य चिकित्सा सेवाओं में नियुक्ति के लिए चुना गया, उन्हें और भी अधिक भुगतान किया गया। कैरियर में उन्नति के प्रॉस्पेक्टस थे। इस आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की मासिक आय रुपये 12,000 प्रति माह से कम तय करना अनुचित होगा। यह और भी अधिक हो सकता था यदि उन्हें सरकारी नौकरी करनी होती या निजी प्रैक्टिस शुरू करनी होती। यदि इस राशि का एक तिहाई हिस्सा मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के रूप में हटा दिया जाए, तो वह आसानी से रुपये 8,000 प्रति माह अपने माता-पिता के लिए बचा सकता था।

(18) ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य पर गौर किया कि दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 23 वर्ष थी। फिर भी, इसने इस परिकल्पना पर 10 का गुणक लागू किया है कि मृतक की शादी 10 साल बाद हो सकती थी। श्री अशोक शर्मा का तर्क है कि ट्रिब्यूनल ने 10 का गुणक लागू करने में गलती की है। उनका कहना है कि 18 का गुणक लागू किया जाना चाहिए।

(19) अदालतें जिस मुख्य सिद्धांत का पालन करती हैं वह यह है कि नुकसान को कम से कम किया जाना चाहिए। फिर भी, हम ज़मीनी हक़ीक़तों से नज़रें नहीं चुरा सकते। यह निर्विवाद है कि जीवन प्रत्याशा वर्षों के साथ बढ़ रही है। इससे भी आगे, भले ही मृतक की शादी हो गई हो, सामान्य घटनाक्रम में वह अपने माता-पिता की देखभाल करता रहेगा और उनका भरण-पोषण करता रहेगा। कम से कम, वह उनके लिए मदद और सांत्वना का स्रोत भी होता। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि दुर्घटना के समय अपीलकर्ता संख्या 1 की आयु लगभग 60 वर्ष थी जबकि अपीलकर्ता संख्या 2 की आयु 58 वर्ष से कम थी। एक सुझाव यह भी है कि अपीलकर्ता फिट और स्वस्थ नहीं हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, हम 12 का गुणक लागू करना उचित समझते हैं।

(20) उपरोक्त के मद्देनजर, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलकर्ताओं को रुपये 96,000 प्रति वर्ष की मौद्रिक हानि हुई है। 12 के गुणक के साथ, यह आंकड़ा रु. 11,52,000 हो जता है। इससे भी आगे, प्रथम अपीलकर्ता ने PW-1 के रूप में अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने परिवहन में रूपये 80,000 और अंतिम संस्कार और दाह संस्कार आदि पर रु. 40,000 की राशि खर्च की थी। बयान के इस हिस्से को जिरह में चुनौती नहीं दी गई थी। सामान्यतः यह राशि भी अपीलकर्ताओं को देय होती। हालाँकि, हमारा मानना है कि कुल मुआवजा 45,000 रु. इस खाते पर उचित और न्यायसंगत होगा।

(21) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(22) चाहे हम मुआवजे की कितनी भी राशि का आकलन करें और अवॉर्ड दें, अपीलकर्ताओं को जो नुकसान हुआ है वह अपूरणीय है। समय के अलावा कोई भी इस घाव को नहीं भर सकता। इस घाव का निशान उनके जीवन के अंतिम दिन तक बना रहेगा। जहां तक इस अपील

का सवाल है, उपरोक्त शर्तों के तहत इसे स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ताओं को ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार दावा याचिका दायर करने की तारीख से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 11,97,000 रुपये की राशि का हकदार माना जाता है। चूँकि दोनों वाहनों को ट्रिब्यूनल द्वारा समान रूप से उत्तरदायी माना गया है और उस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी गई है, प्रतिवादी संख्या 5 और 6 का दायित्व संयुक्त और कई होगा। अपीलकर्ता अपनी लागत के हकदार होंगे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा